

सच्चाई और अच्छाई की
तलाश में पूरी दुनिया घूम
लें, अगर वह खुद के
अंदर नहीं तो कहीं नहीं

वर्ष 03, अंक 15, नई दिल्ली | बुधवार, 26 मार्च 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

03 यह भ्रष्टाचार और अक्षमता के युग को समाप्त करने वाला बजट : सीएम • 06 भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2025 - प्रमुख परिवर्तन और प्रभाव • 08 संस्कारशाला : बड़ों की गरिमा और विनम्रता का महत्व

दौड़ेंगी 5000 बसें, प्रदूषण मुक्त होगी दिल्ली दिल्ली बजट पर सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान

संजय बाटला

दिल्ली सरकार ने अपने बजट में परिवहन के लिए 12952 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसमें से 5000 नई बसें खरीदी जाएंगी और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा शुरू की जाएगी। बजट 2025-26 पेश करते हुए गुप्ता ने घोषणा की कि राजधानी में सार्वजनिक परिवहन और शहरी गतिशीलता में सुधार के लिए 12952 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली की महिलाएं अब बसों में सफर के लिए टिकट के झंझट से बच सकेंगी। सरकार महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा का लाभ दिलाने के लिए यात्रा कार्ड जारी करेगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि भ्रष्टाचार पर लगातार लगे हुए दिल्ली सरकार मौजूदा पिक टिकट प्रणाली की जगह महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा कार्ड जारी करेगी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को बजट में



इसकी घोषणा की है।

परिवहन के लिए 12,952 करोड़ रुपये निर्धारित
बजट 2025-26 पेश करते हुए गुप्ता ने घोषणा की कि राजधानी में सार्वजनिक परिवहन और शहरी गतिशीलता में सुधार के लिए परिवहन क्षेत्र के लिए 12,952 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि मुफ्त बस सेवाओं का उपयोग करने वाली महिलाओं के लिए निर्बाध, भ्रष्टाचार मुक्त अनुभव सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा



गुलाबी टिकटों की जगह एक नया डिजिटल यात्रा कार्ड आएगा। उन्होंने कहा कि यह कार्ड मिलने पर महिलाएं कभी भी सार्वजनिक बसों में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने के लिए अधिकृत हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि बेहतर दक्षता के लिए पूरी प्रणाली को डिजिटल किया जाएगा।

5,000 से अधिक नई बसें होगी शामिल
गुप्ता ने कहा कि हमारा लक्ष्य दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ, विश्वसनीय और

वैश्विक रूप से मजबूत बनाना है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में वर्तमान में 2,152 इलेक्ट्रिक बसें हैं और 2025-26 तक वे 5,000 से अधिक नई बसें शामिल की जाएंगी। गुप्ता ने घोषणा की कि शहर की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से शहरी परिवहन परियोजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के समर्थन से 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, दिल्ली मेट्रो के विस्तार के लिए 2,929 करोड़ रुपये

अलग रखे गए हैं। मुख्यमंत्री ने टैक्सी और ऑटो-रिक्शा चालकों के लिए एक कल्याण बोर्ड स्थापित करने की योजना की भी बात की, जो उनकी कामकाजी परिस्थितियों में सुधार और बेहतर सहायता प्रणाली प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस बीच, 2024-25 के बजट में परिवहन क्षेत्र के लिए दिल्ली सरकार का परिव्यय 9,337 करोड़ रुपये था, जिसमें इस बजट में लगभग तीन हजार करोड़ की वृद्धि हुई है।

अति विशेष सूचना

“परिवहन विशेष” हिन्दी दैनिक समाचार पत्र आर.एन.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त करने के बाद से आपके द्वारा प्राप्त भरपूर सहयोग से मार्च में अपने 2 साल पूरे कर रहा है। इन दो सालों में समाचार पत्र को निष्पक्ष रूप से चलाने में आप सभी का भरपूर सहयोग रहा है जिसके लिए प्रशासनिक विभाग परिवहन विशेष आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता है और आशा करता है की भविष्य में भी आपका सहयोग हमारे साथ ऐसे ही बना रहेगा। इन दो सालों में समाचार पत्र को राष्ट्रीय स्तर पर सभी शहरों और जिलों तक पहुंचाने और वहां की सही और सच्ची खबरें हम तक पहुंचाने वाले रिपोर्टरों का दिल से धन्यवाद। आप सभी को यह जान कर खुशी होगी की “परिवहन विशेष हिन्दी दैनिक समाचार पत्र” का द्वितीय वार्षिकी समारोह अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में सम्पन्न किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सड़कों को जाम और दुर्घटनाओं से मुक्त करवाने के साथ दिल्ली को प्रदूषण मुक्त राज्य का उद्देश्य रखा गया है। इस समारोह में निम्नलिखित मुद्दों पर वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा

1. लेन ड्राइविंग कितनी अनिवार्य?
 2. “सड़क दुर्घटना से कैसे हो सकता है बचाव?”
 3. “दिल्ली को कैसे प्रदूषण मुक्त राज्य बनाया जा सकता है?”
- वाद-विवाद प्रतियोगिता में हिस्सेदारी लेने वाले वक्ताओं के वक्तव्य के साथ परामर्शदाताओं से चर्चा भी इस समारोह में रखी जा रही है। इसके साथ इस आयोजन में भारत देश में निर्मित ई वाहनो, वीएलटीडी संयंत्र, एवम अन्य उपयोगी स्टाल भी सब को आकृषित करने के लिए उपलब्ध होंगे। इस समारोह में
1. सबसे अच्छा विचार / तर्क और समाधान प्रदान करने वाले वक्ता को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा,
 2. परिवहन क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले संगठनों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा,
 3. सड़क सुरक्षा के प्रति कार्य करने वाले संगठनों के पदाधिकारियों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा,
 4. परिवहन विशेषज्ञों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा,
 5. समाचार पत्र से अलग अलग राज्यों से जुड़े एंकर, वीडियो ग्राफर, रिपोर्टर, लेखक, ज्योताचार्य, कवि एवम सहायकों को सम्मानित किया जाएगा।

संजय कुमार बाटला
संपादक

कल के समाचार पत्र में छपी खबर “परिवहन विभाग ने प्रवर्तन शाखा गुप डी और सी कर्मचारियों के लिए 21 मार्च 1997 से आज तक 5वें, 6वें, 7वें वेतन आयोग के अनुसार आर.आर. संशोधन नहीं लागू किया” के लिए परिवहन विभाग ने जारी किया एक आदेश

संजय बाटला

नई दिल्ली। इस आदेश को जारी करने के पीछे कैंट द्वारा जारी एक आदेश है जिसका शीर्षक है श्री हरिंदर सिंह बनाम जीएनसीटी ऑफ दिल्ली एवं अन्य। इस आदेश में विभागों ने कैंट के आदेश का निपटारा करना बताया है। आपकी जानकारी हेतु बता दें की परिवहन विभाग के आला अधिकारी द्वारा प्रवर्तन शाखा के कर्मचारियों और अधिकारियों को जो पदोन्नति दी है उसके अंदर शिकायतें ही शिकायतें हैं और कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आरआर लागू नहीं लिए हैं आपकी जानकारी हेतु परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश का हिन्दी रूपांतर प्रस्तुत है, पढ़ें और जानें

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार परिवहन विभाग: प्रशासन शाखा
5/9 अंडर हिल रोड: दिल्ली: 110054
(वेबसाइट: <http://transport.delhigovt.nic.in>)
क्रमांक
एफ.4/74/प्रशासन/टीपीटी/2024/11/700
दिनांक: 11/03/25
विषय: ओए संख्या 1361/2021 जिसका शीर्षक है श्री हरिंदर सिंह बनाम जीएनसीटी ऑफ दिल्ली एवं अन्य।
बोलने का आदेश
जबकि, श्री हरिंदर सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री टोडा राम इस विभाग में हेड कांस्टेबल (इंफ.) के पद पर कार्यरत हैं। जबकि, उन्हें पैदल कांस्टेबल (इंफ.) के पद पर वेतनमान रु.

775-12-871-14-915-19-1030-20-1150 पर आदेश संख्या एफ.1(5)/94-प्रशासन/टीपीटी/2063-68 दिनांक 04.04.1997 द्वारा 21.03.1997 को नियुक्त किया गया था। जबकि, नियुक्ति आदेश संख्या एफ.1(5)/94-प्रशासन/टीपीटी/2063-68 दिनांक 04.04.1997 को इस सीमा तक संशोधित किया गया था कि अधिकारी को स्वीकृत वेतनमान 775-1150 के स्थान पर 800-1150 रुपए पड़ा जाए। चूंकि, तदनुसार, आदेश संख्या एफ.पी.एफ./एच.-2/एफ.सी./टीपीटी./3584-90 दिनांक 21.09.2004 द्वारा अधिकारी के संशोधित वेतन निर्धारण का आदेश जारी किया गया है। जबकि, आवेदक को दिनांक 12.12.2011 के आदेश संख्या एफ.9(10)/10/प्रशासन/टीपीटी/8318-30 के तहत 07.10.2010 से हेड कांस्टेबल (इंफ.) के पद पर पदोन्नत किया गया था, उसका वेतन अनजाने में ग्रेड पे 1900/- रुपये के (लेवल-2) के साथ तय हो गया था। उसका वेतन 16.10.2017 के MACP आदेश के तहत पुनः निर्धारित/संशोधित किया गया, 01.09.2008 से ग्रेड पे 1900/- रुपये के साथ प्रथम वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया। जबकि, छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के पैरा 7.57.22 के अनुसार रु.7.57.22-दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के ऑपरेशन विंग, प्रदूषण विंग और प्रवर्तन विंग में विभिन्न पदों के लिए उच्च वेतनमान मांगे गए हैं। यह देखा गया है कि इन पदों से जुड़े वर्तमान वेतनमान में कोई

परिवहन विभाग ने प्रवर्तन शाखा गुप डी और गुप सी कर्मचारियों के लिए 21 मार्च 1997 से आज तक 5वें, 6वें, 7वें वेतन आयोग के अनुसार आर.आर. संशोधन नहीं किया

परिवहन विभाग के आला अधिकारी के द्वारा जारी की गई खबर के अनुसार दिनांक 21 मार्च 1997 के आदेश के तहत निम्नलिखित पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को वेतनमान 775-1150 के स्थान पर 800-1150 रुपए पड़ा जाए। चूंकि, तदनुसार, आदेश संख्या एफ.पी.एफ./एच.-2/एफ.सी./टीपीटी./3584-90 दिनांक 21.09.2004 द्वारा अधिकारी के संशोधित वेतन निर्धारण का आदेश जारी किया गया है। जबकि, आवेदक को दिनांक 12.12.2011 के आदेश संख्या एफ.9(10)/10/प्रशासन/टीपीटी/8318-30 के तहत 07.10.2010 से हेड कांस्टेबल (इंफ.) के पद पर पदोन्नत किया गया था, उसका वेतन अनजाने में ग्रेड पे 1900/- रुपये के (लेवल-2) के साथ तय हो गया था। उसका वेतन 16.10.2017 के MACP आदेश के तहत पुनः निर्धारित/संशोधित किया गया, 01.09.2008 से ग्रेड पे 1900/- रुपये के साथ प्रथम वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया। जबकि, छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के पैरा 7.57.22 के अनुसार रु.7.57.22-दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के ऑपरेशन विंग, प्रदूषण विंग और प्रवर्तन विंग में विभिन्न पदों के लिए उच्च वेतनमान मांगे गए हैं। यह देखा गया है कि इन पदों से जुड़े वर्तमान वेतनमान में कोई

विषयगत नहीं हैं। इसलिए, इन पदों के संबंध में केवल संबंधित चालू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन ही लागू होंगे। जबकि, छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार पैदल कांस्टेबल का वेतन वेतन बैंड 1एस 4440-7440 रुपये तथा ग्रेड वेतन 1650 रुपये में संशोधित किया गया है तथा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार पैदल कांस्टेबल का वेतन लेवल-1 के रूप में संशोधित किया गया है। जबकि, आवेदक ने माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष हरिंदर सिंह बनाम दिल्ली सरकार एवं अन्य शीर्षक से ओ.ए. संख्या 1361/2021 दायर किया और निम्नानुसार प्रार्थना की:-

“ए” प्रतिवादियों को एमएसीपी योजना के तहत प्रथम और द्वितीय वित्तीय लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया जाए। वेतन बैंड-1 में 1900 रुपये और 2000 रुपये के ग्रेड वेतन के साथ क्रमशः 01.09.2008 और 21.03.2017 से, सभी परिणामी लाभ यानी बकाया आदि के साथ।
(ख) कोई भी आदेश/अनुदान/निर्देश पारित करना जिसे यह माननीय न्यायाधिकरण न्याय के हित में उचित एवं उपयुक्त समझे।
जबकि, माननीय कैंट ने उक्त ओ.ए. को अनुमति दी और दिनांक 22.07.2021 को आदेश पारित किया, जिसके तहत निम्नानुसार निर्देश दिया गया:-
“5. पूर्वोक्त के मद्देनजर, गुण-दोष के साथ-साथ सीमाओं पर विचार किए बिना, वर्तमान ओए को प्रतिवादियों को यह निर्देश देते हुए निपटारा जाता है कि वे आवेदक के दिनांक 20.03.2020 के पूर्वोक्त अभ्यावेदन (अनुलग्नक-ए) पर विचार करें और उचित तर्कपूर्ण और स्पष्ट आदेश पारित करके, यथासंभव शीघ्रता से और किसी भी मामले में, इस आदेश की प्रति की तारीख से 10 सप्ताह के भीतर इसका निपटारा करें।”
जबकि, माननीय कैंट के दिनांक 22.07.21 के आदेश के अनुसार श्री हरिंदर सिंह, हेड कांस्टेबल (इंफ.) का दिनांक 20.03.2020 का अभ्यावेदन पहले ही निम्नानुसार निपटारा जा चुका है:- श्री हरिंदर सिंह, हेड कांस्टेबल (प्रवर्तन) को एमएसीपी योजना के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन

01.09.2008 से ग्रेड वेतन 1900/- रुपये के साथ प्रदान किया गया और एमएसीपी योजना के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन 21.03.2017 से ग्रेड वेतन 2000/- रुपये के साथ वेतन बैंड-1 (7वें वेतन आयोग के अनुसार स्तर-3) में आदेश संख्या एफ.4(327)/2011/एसीपी-एमएसीपी/प्रशासन/टीपीटी/4817-27 दिनांक 17/07/2017 के तहत प्रदान किया गया और उनका वेतन दिनांक 16.10.2017 के आदेश के तहत तय किया गया है। अब, इसलिए, श्री हरिंदर सिंह, हेड कांस्टेबल (इंफ.) के दिनांक 20.03.2020 के अभ्यावेदन का निपटारा कर दिया गया है।
(प्रशांत गोयल)
एसीएस-कम-आयुक्त, परिवहन दिनांक: 11/03/25
क्रमांक एफ.4/74/प्रशासन/टीपीटी/2024/11/700
जानकारी के लिए प्रतिलिपि:-
1. अपर मुख्य सचिव-सह-आयुक्त, परिवहन विभाग, जीएनसीटी, दिल्ली के निजी सचिव
2. निजी सचिव, एससीओटी (प्रशासन), परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार
3. डीसी (प्रशासन) के निजी सचिव, परिवहन विभाग, जीएनसीटी, दिल्ली
4. संबंधित अधिकारी।
5. गार्ड फाइल.
(डॉ. आशुतोष कुमार श्रीवास्तव) उप निदेशक, (प्रशासन)।

टॉल्वा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइज्ड ट्रस्ट (पंजीकृत)

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasarjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर रैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम-डीएल-0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए-4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉन्सोलेट कार्यालय :- 529, रामपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली 110042

क्या होती है एचएसआरपी, क्यों अनिवार्य है वाहनों में उपयोग, बनवाने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स का होना है जरूरी

भारत में सड़कों पर हर रोज लाखों वाहनों को चलाया जाता है। इन वाहनों पर एक खास तरह की नंबर प्लेट को लगाया जाता है जिसे HSRP कहा जाता है। सरकार की ओर से वाहनों पर HSRP को व क्यों अनिवार्य किया है। यह क्या होती है (What is HSRP) और इसे बनवाने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी होता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में हर रोज हजारों वाहनों की बिक्री की जाती है। इन वाहनों पर अनिवार्य तौर पर HSRP लगाया जाता है। HSRP क्या होती है और क्यों सरकार की ओर से इसे अनिवार्य किया गया है। इसे बनवाने के लिए किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

HSRP को हाई सिक्वोरिटी नंबर प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। पूरे भारत में वाहनों पर इसी नंबर प्लेट के उपयोग को अनिवार्य (vehicle number plate rules) कर दिया गया है। जिस भी गाड़ी पर HSRP नहीं होगी, ट्रैफिक पुलिस ऐसे वाहन को रोककर चालान कर सकती है।

हाई सिक्वोरिटी नंबर प्लेट को एल्यूमिनियम से बनाया जाता है। प्लेट पर बाईं ओर एक होलोग्राम लगाया जाता है इसके अलावा प्लेट पर यूनिंक कोड होता है जिसे लेजर कोड कहा जाता है। इनकी खास बात यह है कि होलोग्राम और लेजर कोड के जरिए उस गाड़ी की पूरी जानकारी निकाली जा सकती है। साथ ही इस कोड को प्लेट से हटाया भी नहीं जा सकता।

इस तरह की नंबर प्लेट की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि चोरी होने के बाद वाहन पर ऐसी प्लेट को नहीं लगाया जा

वाहनों के लिए क्यों जरूरी है HSRP

इसके अलावा अगर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो फिर वाहन से जुड़ी पूरी जानकारी ली जा सकती है।

अगर आपके वाहन पर HSRP नंबर प्लेट लगी हुई है तो भी ट्रैफिक पुलिस की ओर से चालान किया जा सकता है। असल में इस

प्लेट को रिबिट की सहायता से गाड़ी पर लगाया जाता है, जिससे रिबिट तोड़ने की कोशिश करते हुए यह नंबर प्लेट भी खराब हो जाती है और फिर इसका उपयोग किसी अन्य वाहन में नहीं किया जा सकता। लेकिन कई लोग रिबिट की जगह सामान्य नट का उपयोग कर HSRP को अपने वाहन पर लगाते हैं। ऐसी स्थिति में ट्रैफिक पुलिस की ओर से आपका चालान किया जा सकता है।

इस तरह की प्लेट को सही प्रक्रिया के बाद ही बनवाया जा सकता है। जिसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत (HSRP documents required) होती है। एचएसआरपी के लिए वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जिसमें वाहन से जुड़ी पूरी जानकारी होती है। इसके अलावा चैसिस नंबर, इंजन नंबर, वाहन के मालिक को पहचान के लिए आधार, वॉटर कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है।

महिलाओं को समृद्धि, छात्रों को लैपटॉप, 5 रुपये में खाना... भाजपा सरकार के पहले बजट की 10 बड़ी बातें



दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश कर रही हैं। यह 27 सालों बाद दिल्ली में भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा पहला बजट है। सीएम ने अपने भाषण में कहा कि यह बजट बुनियादी ढांचे शिक्षा स्वास्थ्य सेवा परिवहन और प्रदूषण नियंत्रण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश कर रही हैं। बता दें 27 सालों बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा पहला बजट है। सीएम ने अपने भाषण में कहा कि दिल्ली की जनता के लिए इस बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और प्रदूषण नियंत्रण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने वाला बजट है।

सीएम ने कहा पिछली सरकार ने भारी भरकम बजट जरूर रखे मगर झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए कोई योजना नहीं बनाई कोई काम नहीं किया उनकी जिंदगी बद से बदतर होती जा रही थी। प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया जाएगा। जिसमें 20 करोड़ का

आवंटन होगा।

पिछली सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना लागू होने नहीं दी और इसका किसी को लाभ नहीं होने दिया। रेखा गुप्ता ने कहा कि विकास कार्यों के लिए विधायक निर्धि पूरी मिलेंगे।

सीएम रेखा गुप्ता ने AAP पर कसा तंज

सीएम ने कहा कि यह बजट केवल सड़कों पुलों और एलीवेटेड कॉरिडोर बनाने का ही बजट नहीं है बल्कि पूरी दिल्ली की दशा सुधारने का बजट है। सीएम ने AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि आपने शीशमहल बनवाया, हम गरीबों के लिए घर बनवाएंगे।

कहा कि पिछली सरकार और हमारे बजट में बहुत फर्क है पिछली सरकार केवल घोषणाएं करती थी और हम वादे निभाते हैं। आप हाथ की सफाई जानते हो, कूड़े को हम ही साफ कराएंगे। उन्होंने कहा कि आपने अपने लिए लाखों रुपए का शौचालय बनवाया हम झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनवाएंगे। विपक्षी सदस्यों की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप केवल बातें बनाते थे और हम दिल्ली को बनाएंगे।

दिल्ली में उद्योगपति व्यापारी परेशान थे, कोई भी अफसर जाकर

उन्हें धमका देता था और वह परेशान होते थे, दिल्ली का उद्योग पटरी से उतर गया था दिल्ली में व्यापार और निवेश ठप हो गया था, मगर अब प्रधानमंत्री की सोच के तहत दिल्ली में व्यापार और निवेश के द्वार खुले।

बजट की 10 बड़ी बातें

दिल्ली में महिलाओं 2500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। 210 करोड़ गर्भवती महिलाओं को दिए जाएंगे।

जनता को अब 10 लाख का बीमा मिलेगा। जन आरोग्य योजना में 5 लाख का अतिरिक्त बीमा मिलेगा। 50 हजार अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे।

कनेक्टिविटी सुधार के लिए 1 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे। 100 जगह अटल कैटीन। 100 करोड़ का प्राविधान। पांच रुपए की मिलेगी थाली।

दिल्ली में सड़कों के सुधार के लिए 3800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए DUSIB को 696 करोड़ दिए जाएंगे।

दिल्ली में नई औद्योगिक और वेयर हाउसिंग नीति लाई जाएगी।

सीनियर सिटिजनस को देगे चार से पेंडिंग ग्रांट- 20 करोड़ का ग्रांट।

रेखा गुप्ता ने इसे ऐतिहासिक बजट करार देते हुए कहा कि यह भ्रष्टाचार और अक्षमता के युग को समाप्त करने वाला बजट है

मुख्य संवाददाता/ सुष्मा रानी

इस बजट में दिल्ली सरकार ने 100 अटल कैटीन स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। ये कैटीन गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ते और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए बनाई जाएंगी। ऐसे में आज के इस फीचर राइटिंग में जानेगें कि आखिर ये अटल कैटीन क्या हैं और किन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके लिए पढ़ते जाएं इस फीचर राइटिंग को अंत तक।

अटल कैटीन क्या है ?

अटल कैटीन भारत के कई राज्यों में शुरू की गई सस्मिडी वाली भोजनालय हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को किफायती दरों पर भोजन प्रदान करती हैं। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में रखा गया है।

बता दें, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2025 के चुनावी घोषणापत्र में हर झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र में अटल कैटीन शुरू करने का वादा किया था। इन कैटीन में मात्र 5 रुपये में गरमा-गरम पका हुआ भोजन उपलब्ध होगा। यह योजना तमिलनाडु की अम्मा कैटीन और कर्नाटक की इंदिरा कैटीन से प्रेरित है। हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी इस तरह की कैटीन किसानों और मजदूरों के लिए शुरू की

“दिल्ली सरकार का बजट 2025-26 प्रस्तुत करते हुए दिल्ली नगर निगम को उचित फंड वृद्धि दी है”

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है की दिल्ली की मुख्य मंत्री रेखा गुप्ता लम्बे समय तक नगर निगम पार्षद रही हैं और उसी का परिणाम है की उन्होंने दिल्ली सरकार का बजट 2025-26 प्रस्तुत करते हुए दिल्ली नगर निगम को उचित फंड वृद्धि दी है। दिल्ली भाजपा प्रवक्ता ने कहा था की गत वर्ष 2024-25 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री आशिषी माली ने प्राइव्करी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता नदों में दिल्ली नगर निगम को रूपए 3153 करोड़ की राशि आवंटित की थी जबकि सीएम रेखा गुप्ता ने अपने बजट में लगभग 12.5% की वृद्धि देते हुए रूपए 3560 करोड़ दे दिया है। इसी तरह भाजपा सरकार ने बी.टी.ए. नद में दिल्ली नगर निगम को 13% से अधिक की वृद्धि के साथ रूपए 3337 करोड़ दिए हैं जबकि अरविंद केजरीवाल सरकार ने गत वर्ष केवल रूपए 2955 करोड़ दिए थे। इसके अतिरिक्त दिल्ली नगर निगम गत अनेक वर्षों से दिल्ली की केजरीवाल सरकार से स्थाय द्यूटी एवं पार्किंग शुल्क का पूरा हिस्सा देने की मांग कर रहा था जिसे आज सीएम रेखा गुप्ता सरकार ने पूरा किया है। पहले की से तरह गत वर्ष भी दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने स्थाय द्यूटी एवं पार्किंग शुल्क के के नद में दिल्ली नगर निगम को मात्र रूपए 2315 करोड़ दिए थे जिसे मुख्य मंत्री रेखा गुप्ता ने वास्तविक आधार पर रूपए 3640 करोड़ किया है।

गई है, जहां 100 रुपये में चपाती, चावल, दाल और सब्जी दी जाती है।

बजट की मुख्य विशेषताएं

रेखा गुप्ता ने विधानसभा में कहा कि यह बजट दिल्ली को विकसित दिल्ली की ओर ले जाएगा। इसमें बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय को दोगुना कर 28,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। सड़क, सीवर सिस्टम, और जल आपूर्ति जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, महिला समृद्धि योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये और एनसीआर

क्षेत्र से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए 1,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

दिल्ली के लिए एक नई शुरुआत
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, “यह साधारण बजट नहीं है। यह खराब अर्थव्यवस्था से उबरकर विकास की ओर बढ़ने का बजट है।” अटल कैटीन जैसी योजनाएं न केवल भूख मिटाने में मदद करेंगी, बल्कि गरीबों के जीवन स्तर को भी ऊंचा उठाएंगी। यह बजट दिल्ली के विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है।

दिल्ली के किसानों की मौज, अब 6000 की जगह मिलेंगे 9000

27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी करने वाली भाजपा सरकार ने मंगलवार को अपना पहला बजट पेश किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट पेश करते हुए अपने चुनावी वादों पर फोकस किया। सीएम रेखा गुप्ता ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया जो आप सरकार के पिछले बजट से लगभग 31 प्रतिशत अधिक है।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में अपनी सरकार का पहला बजट पेश किया। सीएम ने इस बजट में दिल्ली वालों को कई सौगातें दीं। दिल्ली की किसानों को अब 6000 रुपये की जगह 9000 रुपये मिलेंगे। इसके लिए दिल्ली के बजट में पीएम किसान सम्मान निधि के लिए 5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बता दें कि अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते हैं।

दिल्ली के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का बजट

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का इस वित्तीय वर्ष का बजट 1 लाख करोड़ रुपये होगा, जो आम आदमी पार्टी सरकार के पिछले बजट की तुलना में 31.5 प्रतिशत ज्यादा है।

मुख्यमंत्री ने कहा, रिपिछली सरकार ने विकास पर कम खर्च किया और कहा कि हमारे पास बजट और फंड नहीं है। यह पैसे की कमी नहीं थी, बल्कि राजनीतिक कारणों से उन्होंने दिल्ली का विकास नहीं किया। वे दिल्ली और लोगों के लिए काम नहीं करना चाहते थे। उनके निजी राजनीतिक एजेंडे के कारण पूरी दिल्ली को नुकसान उठाना पड़ा।

यमुना की सफाई के लिए 9000 करोड़ रुपये आवंटित
दिल्ली सरकार ने सीवर के विकास, पानी की सफाई और यमुना नदी के लिए 9000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, यह घोषणा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में की है। दिल्ली सरकार के बजट में भाजपा के चुनाव संकल्प पत्र में किए गए कई वादों पर फोकस किया गया।

‘मेक इन इंडिया’ को अब ‘मेक एआई इन इंडिया’ तक विस्तार किया जाना चाहिए : राघव चड्ढा

मुख्य संवाददाता/ सुष्मा रानी

नई दिल्ली। राज्यसभा में जोरो आवर के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने वैश्विक एआई दौड़ में भारत की स्थिति पर चिंता जताई और चेतावनी दी कि जहां अमेरिका और चीन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं भारत पिछड़ सकता है। उन्होंने एआई निवेश और पेटेंट में भारी अंतर को उजागर किया, जबकि भारत वैश्विक एआई कार्यबल का 15 फीसद योगदान देता है। सांसद ने जोर देकर कहा कि भविष्य में ‘विश्वगुरु’ वही देश होगा जो स्वदेशी एआई में मजबूत होगा और ‘मेक इन इंडिया’ के साथ-साथ हमें ‘मेक एआई इन इंडिया’ की ओर बढ़ना चाहिए।

राघव चड्ढा ने कहा कि एआई भारत के उभरते हुए भविष्य के लिए जरूरी है। अमेरिका के पास चैटजीपीटी, जेमिनी, एन्थ्रोपिक, ग्रेक हैं। चीन के पास डीपसीक है, जो सबसे शक्तिशाली और किफायती है। लेकिन सवाल यह है कि एआई की इस दुनिया में भारत कहाँ है? क्या भारत इसमें पिछड़ना रहेगा और अपना एआई मॉडल नहीं बना पाएगा?

राघव चड्ढा ने पेटेंट में अंतर को रेखांकित करते हुए कहा कि 2010 से 2022 तक अमेरिका ने दुनिया के 60 फीसद और चीन ने 20 फीसद एआई पेटेंट दाखिल किए, जबकि भारत ने सिर्फ 0.5 फीसद पेटेंट दाखिल किए। उन्होंने भारत की क्षमता पर जोर देते हुए कहा

कि भारत में सबसे अधिक योग्यता और मेहनती प्रतिभा है। हम वैश्विक एआई कार्यबल का 15 फीसद योगदान देते हैं, जिसमें 4.5 लाख पेशेवर विदेश में काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भारत में दुनिया में तीसरा सबसे अधिक एआई कौशल प्रवेश (स्किल पेंट्रेशन) है। हमारे पास कौशल, प्रतिभा, मेहनती लोग, विशाल डिजिटल अर्थव्यवस्था और 90 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। फिर भी हम एआई के केवल उपभोक्ता बन गए हैं, निर्माता नहीं।

उन्होंने ओपनएआई के संस्थापक के हालिया बयान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे भारत के एआई भविष्य को लेकर पूरी तरह निराश हैं। राघव चड्ढा ने जोर दिया कि हमें इसका जवाब देना होगा और एआई का निर्माता बनना होगा, जिसके लिए कुछ कदम उठाने जरूरी हैं।

सांसद ने भारत को एआई महाशक्ति बनाने का रोडमैप पेश करते हुए कहा कि भारत को स्वदेशी एआई चिप्स और उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करना चाहिए ताकि घरेलू नवाचार को बढ़ावा मिले। इसके लिए एक समर्पित एआई इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड की जरूरत होगी। भारतीय संस्थानों और एआई स्टार्टअप्स को उदार अनुसंधान अनुदान दिए जाएं और शीर्ष एआई प्रतिभा को भारत में रोकने के लिए प्रतिस्पर्धी अवसर, इन्फ्रास्ट्रक्चर और



प्रोत्साहन दिए जाएं।

उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय एआई स्टार्टअप्स को बड़े पैमाने पर मौजूदा डेटा तक पहुंच दी जानी चाहिए, जो मेटा और गूगल के पास हैं लेकिन भारतीय कंपनियों के पास नहीं। उन्होंने निवेश बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि अमेरिका ने एआई के लिए 500 बिलियन डॉलर से अधिक, चीन ने 137 बिलियन डॉलर से अधिक खर्च किए हैं, जबकि भारत का मिशन केवल एक बिलियन डॉलर का है। अमेरिका अपनी जीडीपी का 3.5 फीसद और चीन 2.5 फीसद अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) पर खर्च करता है, जबकि

भारत केवल 0.7 फीसद खर्च करता है।

राघव चड्ढा ने निष्कर्ष में कहा कि भविष्य में ‘विश्वगुरु’ वही देश होगा जो स्वदेशी एआई में मजबूत होगा। मेक इन इंडिया के साथ-साथ हमें ‘मेक एआई इन इंडिया’ की ओर बढ़ना चाहिए।

उन्होंने चेतावनी दी कि एआई केवल तकनीक नहीं है, यह आर्थिक शक्ति, राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता का मामला है। हम विदेशी एआई मॉडल्स पर निर्भर नहीं रह सकते। भारत को अपना खुद का निर्माण करना होगा।

भारत को एआई महाशक्ति बनाने के लिए राघव चड्ढा के सुझाव

दिल्ली में होमगार्ड की संख्या बढ़ाने से सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को दिये आश्वासन की पूर्ति का रास्ता खुला : वीरेन्द्र सचदेवा

मुख्य संवाददाता/ सुष्मा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की दिल्ली की भाजपा सरकार का बजट 2025-26 दिल्ली के चौहमुखी विकास के साथ ही आम नागरिकों के लिए बेहतर जीवन देने को समर्पित है।

वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की जहां अरविंद केजरीवाल सरकार गत तीन वर्ष से दिल्ली बजट की कुल राशि को गिरा रही थी वहीं सीएम रेखा गुप्ता सरकार के पहले बजट ने 31.5% की वृद्धि के साथ बजट की कुल राशि को 1 लाख करोड़ रूपये को पार करने के साथ ही सरकार के कैपिटल खर्च को

लगभग दुगना करते हुए 15089.25 करोड़ रूपए से बढ़ा कर 28115.48 करोड़ रूपए पर पहुंचा दिया है जिससे दिल्ली के विकास के साथ साणानय रखरखाव में भी वृद्धि होगी।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है की सीएम रेखा गुप्ता का बजट 2025-26 भाजपा के संकल्प पत्र की पूर्ति कर रहा है, बजट में महिला समृद्धि योजना, प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना में डबल बीमे के साथ महिला सुरक्षा के लिए 3.30 लाख सी.सी.टी.वी. के साथ ही, ड्यूसिब बजट को 3 गुणा बढ़ा कर स्लम क्षेत्रों के सुधार के बम्पर कदम उठाये गये हैं।

दिल्ली में होमगार्ड की संख्या को 10285



से बढ़ा कर 25000 करने के प्रस्ताव से सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को दिये आश्वासन की पूर्ति का रास्ता खुला है।

शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिये सीएम रेखा गुप्ता सरकार ने योजनाबद्ध बजट आवंटित कर दिल्ली के सरकारी स्कूलों एवं अस्पतालों के इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार के साथ ही मूलभूत शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर सुधार के कदम उठाये हैं।

बजट में यमुना सफाई, एस.टी.पी. निर्माण के साथ ही, पर्यावरण सुधार के लिए भी योजनाबद्ध बजट लाकर सरकार ने पर्यावरण सुधार के चुनाव संकल्प की पूर्ति की है।

मां यमुना को मिल जाएगी प्रदूषण से मुक्ति, नहीं गिरेंगे गंदे नाले; सफाई पर खर्च होगी बड़ी रकम

दिल्ली में यमुना नदी को अब नई पहचान मिलेगी। यमुना प्रदूषण से मुक्त हो सकेगी। इसके लिए बजट में बड़ा एलान किया गया है। सभी एसटीपी का उन्नयन कर बढ़ाई जाएगी क्षमता व गुणवत्ता मरम्मत व देखरेख पर ध्यान रहेगा। पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान यमुना नदी को दिल्ली की पहचान बनाने का वादा किया था।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। यमुना की सफाई प्रमुख चुनावी मुद्दा रहा है। प्रधानमंत्री ने इसे निर्मल व अविरल करने, साबरमती रिवर फ्रंट की तरह इसके तट को विकसित करने और इसे दिल्ली की पहचान बनाने का वादा किया था।

पाटी के चुनाव संकल्प पत्र में भी यमुना को स्वच्छ करने का संकल्प था। भाजपा सरकार की सरकार बनने के साथ ही इस संकल्प को पूरा करने के लिए यमुना की सफाई शुरू हो गई है। बजट में भी इसे लेकर बड़ी घोषणा की गई है। नदी में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण नालों व सीवर का पानी गिरना है। इसके समाधान के लिए 40 विकेंद्रीकृत सीवेज उपचार संयंत्रों (डीएसटीपी) बनाने और चालू सीवेज उपचार संयंत्रों

(एसटीपी) के उन्नयन की घोषणा की गई है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने बजट भाषण में कहा, यमुना सिर्फ एक नदी नहीं है, यह हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत है। यमुना की सफाई हमारे संकल्प पत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस बजट में भी यह सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यमुना में नाले का गंदा पानी न गिरे।

इसे सुनिश्चित करने के डीएसटीपी बनने। इससे सीवेज को उसके स्रोत पर ही उपचार किया जा सके। अभी दिल्ली में 38 एसटीपी हैं। इसमें से आधे से अधिक अपनी क्षमता व मानक के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। इनका उन्नयन कर क्षमता व गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी। इनकी मरम्मत व देखरेख पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए पर्याप्त धन आवंटित किया गया है।

सीवर प्रणाली सही नहीं होने के कारण भी यमुना प्रदूषित हो रही है। बरसाती नालों के माध्यम से सीवेज नदी में पहुंच रहा है। इसके समाधान के लिए नए क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाने के साथ ही पुरानी सीवर लाइन बदलने, सीवर लाइन व यमुना की सफाई के लिए आधुनिक मशीन व अन्य उपकरण खरीदने की घोषणा की गई है।

कई नाले का गंदा पानी सीधे यमुना में गिरता है। इन नालों के गंदा पानी को मोड़कर एसटीपी तक पहुंचाया जाएगा जिससे कि उसे शोधित किया जा सके। नजफगढ़ नाला से यमुना में सबसे अधिक प्रदूषण होता है। इसके समाधान के लिए भी काम होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा, राजधानी में जल और सीवेज बुनियादी ढांचे का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप लाने के लिए केंद्र से 2,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है। इससे पानी आपूर्ति सुधारने, शहर में स्वच्छता को बेहतर करने के साथ ही यमुना को साफ करने में मदद मिलेगा।

यमुना की सफाई के लिए आवंटित धन (करोड़ रुपये)
डीएसटीपी बनाने के लिए - 500
नालों के गंदे पानी को उपचार के लिए एसटीपी तक ले जाने की परियोजना - 250
प्रदूषण डूबने के परिवर्तन व इंटरसेप्शन परियोजना -200
यमुना की सफाई के लिए आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए -40
सीवेज व्यवस्था सुधार के लिए सुपर सकर मशीन व अन्य मशीन -20

दिल्ली में 100 जगहों पर खुलेगी अटल कैटीन, बस 5 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना



दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में अपनी सरकार का पहला बजट पेश किया। उन्होंने महिला समृद्धि योजना से लेकर आयुष्मान योजना तक कई योजनाओं के लिए बजट प्रस्तावित किया है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में अपनी सरकार का पहला बजट की। उन्होंने महिला समृद्धि योजना से लेकर आयुष्मान योजना तक कई योजनाओं के लिए बजट प्रस्तावित किया है। सीएम ने दिल्ली के 100 अलग-अलग जगहों पर अटल कैटीन खोलने की बात कही है। इसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

जिसमें हर गरीब लोगों को सिर्फ पांच रुपए में भोजन की थाली दी जाएगी। 'आपने शीशमहल बनवाया, हम गरीबों के लिए घर बनवाएंगे' इस दौरान सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी को मिले एक-एक वोट का हिसाब दूंगी और दिल्ली वालों के लिए काम करके दिखाऊंगी। दिल्ली वालों की दीदी रेखा हूँ, काम करके दिखाऊंगी। सीएम ने आगे कहा कि पिछली सरकार और हमारे बजट में बहुत फर्क है। पिछली सरकार केवल घोषणाएं करती थी और हम वादे

निभाते हैं। आम आदमी पार्टी पर करारा हमला बोलते हुए सीएम रेखा ने कहा कि आपने शीशमहल बनवाया, हम गरीबों के लिए घर बनवाएंगे।

चुनाव के समय भाजपा ने किया था चुनावी वादा
बता दें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के चुनावी घोषणापत्र में एक बड़ा एलान किया था। जिसमें नड्डा ने दिल्ली के झुग्गियों में अटल कैटीन खोलने की बात कही थी। जिसमें गरीबों को सिर्फ 5 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाएगा। नड्डा ने बताया था कि इस कैटीन में गरीबों को पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराई जाएगी।

नड्डा ने कहा कि गरीबों के लिए सभी झुग्गी बस्तियों में अटल कैटीन योजना के अंतर्गत पांच रूपये में पौष्टिक भोजन मिलेगा। आम आदमी पार्टी ने 100 कैटीन खोलने का वादा किया था जिसे पूरा नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार बनते ही गरीबों के लिए सबसे पहले सस्ती दरों पर भोजन का इंतजाम किया जाएगा।

पानी की आपूर्ति में घोटाला दूर करने के लिए पानी की टैंकरों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा। सीवर समस्या दूर करने के लिए राय लेने के लिए 10 करोड़ का बजट रखा गया। पानी की चोरी रोकने के लिए नया सिस्टम लगाने पर डेढ़ सौ करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। टिकट के नाम पर भ्रष्टाचार बंद होगा, महिलाओं को बसों में टिकट नहीं लेना पड़ेगा, उन्हें एक कार्ड दिया जाएगा, जिससे वह यात्रा कर सकेंगी।

नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाना होगा बेहद आसान, नई कनेक्टिविटी से 16 किमी कम होगी दूरी

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच नई कनेक्टिविटी बनने से सफर बेहद आसान होगा जाएगा। साथ ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाली नई कनेक्टिविटी से यातायात भार कम होगा और यात्रा दूरी 16 किमी कम हो जाएगी। एलजी चौक से एक्सप्रेसवे की दूरी अब केवल 5 मिनट में पूरी हो सकेगी। इस प्रोजेक्ट पर 147 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

नोएडा। नोएडा-ग्रेटर नोएडा दोनों शहरों को जोड़ने के लिए नई कनेक्टिविटी तैयार हो रही है, जिसके तहत हरनंदी पर पुल की एप्रोच रोड का काम चल रहा है, जो अगस्त तक पूरा होगा। यह एप्रोच रोड हरनंदी पुल से नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की 45 मीटर सर्विस रोड तक करीब 623 मीटर तक बनाई जा रही है।

पूरे प्रोजेक्ट पर कितने करोड़ होंगे खर्च?

कंपनी ने आठ फरवरी को निर्माण शुरू किया था। इसके बनने के बाद ग्रेटर नोएडा के एलजी चौक से एक्सप्रेसवे तक की दूरी



महज पांच मिनट में पूरी की जा सकेगी। पहले यह दूरी तय करने में 16 किमी अतिरिक्त चलना पड़ता था। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 147 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

इन सेक्टरों को मिलेगा इसका लाभ
एलजी चौक से एक्सप्रेसवे तक यह लिंक 2,090 मीटर लंबा है। इसे 60 मीटर चौड़ा बनाया जा रहा है। इस लिंक रोड पर एक पुल हरनंदी पर सेतु निगम बना रहा है। यह पुल

नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सहभागिता से बनाया गया है। ग्रेटर नोएडा की एप्रोच रोड ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और नोएडा प्राधिकरण बना रहा है।

प्राधिकरण का एरिया करीब 1,020 मीटर का है। इसमें 45 मीटर चौड़ी सड़क एप्रोच रोड 623 मीटर की है। दिल्ली और नोएडा से एक्सप्रेसवे होते हुए परी चौक, एलजी चौक, कलकट्टे, सूरजपुर, सेक्टर

गामा एक, गामा दो, बीटा एक, बीटा दो, उद्योग विहार, उद्योग विहार एक्सटेंशन, गाजियाबाद को जाने वाले लोगों को 16 किमी अतिरिक्त चलना पड़ता था। इसके बनने से दूरी कम होगी। कई सेक्टरों को इसका लाभ मिलेगा।

क्या होगा खास?

62 करोड़ रुपये में पुल का निर्माण किया जा रहा है।

सेतु की लंबाई 210 मीटर है। इसको बनाने में 62.40 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने 25 जनवरी 2019 में किया था।

नोएडा की ओर बनाई जाने वाली इस एप्रोच रोड की ऊंचाई 5.50 मीटर से 8.50 मीटर तक है।

वहीं ग्रेटर नोएडा की ओर परियोजना की लंबाई 1070 मीटर है।

नोएडा एयरपोर्ट के पास अवैध निर्माण पर जमकर गरजा बुलडोजर, 32 अवैध निर्माण कराए ध्वस्त

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास तीसरे चरण में अधिग्रहित होने वाली भूमि पर बने अवैध निर्माणों को यमुना प्राधिकरण ने ध्वस्त कर दिया। सोमवार दोपहर बाद तीन बजे प्रशासन और प्राधिकरण की टीमें भारी पुलिस फोर्स के साथ सीधे किशोरपुर गांव पहुंची और 32 निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। नोएडा एयरपोर्ट के तीसरे चरण में जेवर के 14 गांव की 2053 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। अधिकांशों ने बताया कि योडा के अधिसूचित क्षेत्र के गांव में बिना किसी अनुमति के मुआवजा और प्लॉट के लालच में बाहरी लोगों ने निम्न गुणवत्ता के मिट्टी के महल बनाकर खड़े कर दिए।

जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास तीसरे चरण में अधिग्रहित होने वाली भूमि पर यमुना प्राधिकरण की बिना अनुमति बनाए गए मिट्टी के महलों पर सोमवार को बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई हुई। सोमवार दोपहर बाद तीन बजे प्रशासन और प्राधिकरण की टीमें भारी पीएसी और पुलिस फोर्स के साथ सीधे किशोरपुर गांव पहुंची और अवैध निर्माणों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया।

इस दौरान कुछ लोग अपने अधिवक्ताओं के साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रुकवाने के लिए पहुंचे लेकिन कार्रवाई में जुटी टीमों ने

कार्रवाई को वैध बताते हुए रोकने से साफ मना कर दिया। ध्वस्तीकरण की खबर पूरे क्षेत्र में आने की तरह फैल गई लोगों की भारी भीड़ कार्रवाई को देखने के लिए उमड़ने लगी। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स ने सभी को कार्रवाई स्थल से दूर करते हुए शाम छह बजे तक 32 निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। नोएडा एयरपोर्ट के तीसरे चरण में जेवर के 14 गांव की 2053 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। अधिकांशों ने बताया कि योडा के अधिसूचित क्षेत्र के गांव में बिना किसी अनुमति के मुआवजा और प्लॉट के लालच में बाहरी लोगों ने निम्न गुणवत्ता के मिट्टी के महल बनाकर खड़े कर दिए।

मुख्य सचिव ने एयरपोर्ट निरीक्षण के बाद योडा को पत्र लिखते हुए अवैध निर्माण को रोकने और कार्रवाई के आदेश दिए थे, जिसके बाद योडा ने अवैध निर्माण को हटाने के लिए नोटिस जारी किए लोगों ने स्वयं निर्माण न हटाने पर ध्वस्तीकरण के आदेश जारी कर कार्रवाई शुरू कर दी। सोमवार सुबह से ही प्रशासन और प्राधिकरण की टीमें जेवर कोतवाली में पहुंच गईं।

'यूपी पुलिस से बाकी राज्य भी सीखें', पूर्व डीजीपी संजय कुंडू ने पॉडकास्ट में दिया बड़ा बयान



यूपी पुलिस के पॉडकास्ट बियॉन्ड द बैज के नौवें एपिसोड में हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी संजय कुंडू ने डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्तिमोहन अवस्थी से बातचीत की। कुंभ से लेकर अपनी महकमे में भर्ती देश-विदेश में तैनाती जल संसाधन मंत्रालय में हुए नीति फैसलों को लेकर अनुभवों को साझा किया। इस एपिसोड को यूपी पुलिस ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया है।

नोएडा। उत्तर प्रदेश पुलिस के पाडकास्ट बियांड द बैज का नौवां एपिसोड में जिले में शूट हुआ। इसमें हिमाचल प्रदेश के पूर्व डीजीपी संजय कुंडू से डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्तिमोहन अवस्थी ने बात की।

पूर्व डीजीपी ने कुंभ से लेकर अपनी महकमे में भर्ती, देश-विदेश में तैनाती, जल संसाधन मंत्रालय में हुए नीति फैसलों को लेकर अनुभवों को साझा किया। उधर, यूपी पुलिस को और से एपिसोड को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में अपने अनुभव किए साझा

30 मिनट 36 सेकंड के एपिसोड में संजय कुंडू ने महाकुंभ में श्रद्धालु और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि सफल आयोजन को प्रदेश सरकार और महकमा बधाई का पात्र

है। देश विदेश में बृहद स्तर पर भीड़ प्रबंधन का अनूठा उदाहरण पेश किया है।

यह एक युद्ध स्तर जैसा अनुभव था। यूपी पुलिस ने दो माह तक देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या बल को बिना थके, बिना रूके व बिना डरे संभाला। अमूमन इस तरह के चैलेंज को आर्मी डील करती है। इस अनुभव को अन्य राज्य पुलिस को सिखाया व पढ़ाया जाना चाहिए।

वैश्विक स्तर पर सराहनीय और अनूठा आयोजन

उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि मैनेजिरियल और हाइलेवल लीडरशिप जैसी दो तरह की क्षमताएं होती हैं। यह सब आयोजन में देखने को मिला। मुख्यमंत्री व डीजीपी यूपी ने आयोजन में दृष्टिकोण, नेतृत्वक्षमता, डेलीगेशन, विश्वास, तकनीक का प्रयोग, धैर्य, श्रद्धालुओं के प्रति सम्मान जैसी विशेषताओं के उदाहरण पेश किए।

इसके चलते आयोजन सफल रहा। इससे उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश की साख बढ़ी है। यह वैश्विक स्तर पर सराहनीय और अनूठा आयोजन है। दुनिया से इसका साक्षात्कार कराने के लिए इसका डॉक्यूमेंटेशन और सिरियल भी शूट किया जाना चाहिए। सरकार को लेशन लैन जैसी पहल भी होनी चाहिए। जिससे प्यूचर जेनरेशन पुलिसिंग को भी मदद मिल सके।

नोएडा वाले ध्यान दें! 20 दिन बंद रहेगी शाहबेरी रोड, परेशानी से बचने के लिए इन रास्तों का करें इस्तेमाल

ग्रेटर नोएडा में शाहबेरी रोड के चौड़ीकरण का काम 25 मार्च से शुरू हो गया है। गाजियाबाद को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने वाली 3 किलोमीटर लंबी इस सड़क को दोनों तरफ करीब 1.5 मीटर चौड़ा किया जाएगा। सड़क चौड़ीकरण का काम 20 दिन में पूरा हो जाएगा। सड़क चौड़ी होने के बाद लोगों के लिए क्रॉसिंग रिपब्लिक आना-जाना आसान हो जाएगा।

ग्रेटर नोएडा। शाहबेरी मार्ग के चौड़ीकरण का काम आज से शुरू हो जाएगा। लगभग तीन किलो मीटर लंबी इस सड़क की चौड़ाई दोनों तरफ डेढ़-डेढ़ मीटर बढ़ाई जाएगी। अगले 20 दिन तक इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से बाधित रहेगा।

ट्रैफिक पुलिस ने किया रूट डायवर्जन
वाहन चालकों को सहूलियत के लिए ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन किया है। इसकी एडवाइजरी पूर्व में जारी की जा चुकी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इटेडा गोलचक्कर से क्रॉसिंग रिपब्लिक तक शाहबेरी मार्ग की चौड़ाई अभी तीन मीटर के लगभग है। एक लेन की सड़क होने के कारण यहां अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है।

इसको देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस मार्ग को चौड़ा करने की तैयारी पूरी कर ली है। यह काम आज से शुरू हो जाएगा। मंगलवार



सुबह 10 बजे के बाद आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। प्राधिकरण के प्रबंधक नीतीश कुमार ने बताया कि विकास कार्य के चलते शाहबेरी मार्ग 25 मार्च से 20 दिन के लिए बंद रहेगा। इस दौरान रूट डायवर्ट रहेगा।

इन वैकल्पिक मार्गों का करें इस्तेमाल
ट्रैफिक पुलिस द्वारा रूट डायवर्जन के संबंध में जारी की गई एडवाइजरी के मुताबिक इटेडा गोलचक्कर से शाहबेरी होते हुए गाजियाबाद की ओर जाने वाले वाहन गौड़ चौक से तिगरी गोलचक्कर की ओर 130 मीटर सड़क से होते हुए गंतव्य की ओर जा सकेंगे।

तिलपता से शाहबेरी होते हुए गाजियाबाद की ओर जाने वाले वाहन एकमूर्ति गोलचक्कर से दाहिने मुड़कर रोजा चौका से छपरोला रेलवे फाटक से लाल कुआं होते हुए गंतव्य की ओर जा सकते हैं।

वहीं एबीईएस, गाजियाबाद/एनएच-24 की ओर से शाहबेरी होते हुए नोएडा ग्रेटर नोएडा की ओर आने वाले वाहन शाहबेरी के रास्ते से न आकर एनएच-24 विजयनगर बाईपास मार्ग से 130 मीटर चौड़ी सड़क से तिगरी गोलचक्कर होते हुए गौड़ चौक से गंतव्य की ओर जा सकते हैं।

26 मार्च की रात तीन घंटे रहेगा डायवर्जन

उधर, ऊर्जा निगम की ओर से सेक्टर 132 स्थित सिफ्री डेटा सेंटर परिसर तक विद्युल लाइन बिछाने संबंधी कार्य के चलते 26 मार्च की रात करीब साढ़े छंटे तक रूट डायवर्जन रहेगा।

डीसीपी यातायात लखन सिंह यादव ने बताया कि ऊर्जा निगम की ओर से 26 मार्च की रात एक बजे सुबह साढ़े चार बजे तक सेक्टर

45 रोड (निकट आमपाली चौकी) पर सबस्टेशन से सेक्टर 132 सिफ्री डेटा सेंटर तक 220 केवी लाइन की ओवरहेड लाइन बिछाने जाने व तार बदले जाने का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

सेक्टर 98, 100 व 104 तिराहा और एक्सप्रेसवे डबल लेन सर्विस रोड से आमपाली चौकी सेक्टर 45 की ओर जाने वाले यातायात पर रूट डायवर्जन रहेगा।

सेक्टर 44 गोलचक्कर से एक्सप्रेसवे डबल लेन सर्विस रोड से सेक्टर 45, 98, 100 व 104 की ओर जाने वाला यातायात हाजीपुर चौक होकर आगे की ओर जाएगा।

सेक्टर 100 व 104 से सेक्टर 45 होकर सेक्टर 44 की ओर जाने वाला यातायात हाजीपुर चौक से डबल लेन सर्विस रोड होकर आगे की ओर भेजा जाएगा।

कचरा-कचरा जिंदगी, समस्या और समाधान

कुलभूषण उपमन्यु

एकमुखी समाधान से काम नहीं चलेगा। स्थानीय स्थितियों के अनुसार विविध प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके लिए प्लास्टिक बनाने और प्लास्टिक में पैक सामान बेचने वाली कंपनियों को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उन्हें नवाचार के लिए फंड खड़ा करना चाहिए।

वर्ष 2019 में हिमाचल, जिसका नाम आते ही मन में एक चित्र उभरता है। निर्मल जल, स्वच्छ वायु, सुंदर चरागाह, चंद्र और फैली हरितिमा, ऊंचे दर्रे, हिमाच्छादित गिरि शिखर, भौगोलिक विविधता, कल-कल बहती नदियां, समृद्ध वन एवं वन्य जीवन, आधुनिक आवागमन साधन, पर्याप्त आवास सुविधाएं, अनेक धार्मिक स्थल, रमणीय स्थल और सहयोगी स्वभाव के पर्वतवासी समुदाय, यानी पर्यटन के लिए आदर्श एवं सुरक्षित क्षेत्र। निःसंदेह हिमाचल ऐसा ही है। किंतु पर्यटन के साथ-साथ सूखे कचरे का भी विस्तार होता जा रहा है, जो हिमाचल के आदर्श, सौंदर्यपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य को प्रसिद्ध करता जा रहा है। जगह-जगह कचरे के ढेर देख कर आदमी असहाय महसूस करने लगता है। स्वच्छता अभियान के चलते बड़े पैमाने पर शौचालय निर्माण का कार्य सफलतापूर्वक किया गया, जिसका परिणाम भी सुखद हुआ। किंतु सूखे कचरे के निष्पादन की दिशा में हालात दिन-प्रतिदिन खराब ही होते जा रहे हैं। क्या शहर और क्या गांव? शहरों से कचरा उठा कर डंपिंग स्थलों तक पूरा जा नहीं पाता। जो जा पाता है, उसके उपचार की व्यवस्थाएं अपर्याप्त हैं।

सबसे ज्यादा समस्या प्लास्टिक कचरे से पैदा हो रही है। वैसे तो यह सार्वभौमिक समस्या बन गई है, किंतु पर्वतीय क्षेत्रों के लिए तो यहां की पर्यटन पर

आधारित आजीविका के लिए ही खतरा पैदा हो गया है। इस समय दो करोड़ के लगभग पर्यटक वर्षभर में आते हैं। यानी यहां की जनसंख्या से तीन गुणा। सरकार इस संख्या को पांच करोड़ करना चाहती है। आर्थिक दृष्टि से यह आजीविका और परकारी आय के लिए लाभप्रद ही सिद्ध होने वाला है। किंतु पर्यटन अपने साथ अनेक समस्याएं और प्रकृति पर दबाव भी लाता है। इनमें से कचरे की मात्रा में बढ़ोतरी भी अवश्यभावी समस्या है। वर्तमान कचरा प्रबंधन की स्थिति देख कर लगता है कि हम आने वाले दबाव को कैसे झेल पाएंगे, जबकि वर्तमान स्थिति को ही हम संभालने में असमर्थ सिद्ध हो रहे हैं। शहरों में भी कचरा जगह-जगह खुले में जलाने के दृश्य देखे जा सकते हैं। यहां तक कि कचरा निष्पादन स्थलों में भी कचरा जलाया जाता है। यह सीधा बीमारी को निमंत्रण है। गांव की तो हालत और भी खराब है। आजकल ज्यादातर दैनिक जरूरतों के सामान पैकिंग में ही आते हैं। कुरकुरे, नमकीन, चिप्स, चॉकलेट, करियाने का सामान, दूध, दही, सब प्लास्टिक में ही पैक होकर आ रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर पाबंदी के बावजूद यह सब पैकिंग का कचरा तो आ ही रहा है, इसके साथ सब्जियों का बाहरी राज्यों से जो आयात हो रहा है, वह ज्यादातर प्लास्टिक की पन्तियों में ही हो रहा है। इस तरह कचरे के अंबार तो बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर चिकित्सा से जुड़ी सामग्री, बिजली के बल्ब, बैटरियां, इलेक्ट्रॉनिक सामान शहरों से लेकर गांव तक चारों ओर फैलते जा रहे हैं। खेत-खलिहान, कूहलें, वन क्षेत्र कचरे की चपेट में हैं। जब तक कोई निश्चित व्यवस्था खड़ी नहीं होती, तब तक लोगों को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि विकल्प देकर ही सख्ती भी की जा सकती है। उसके बिना तो लोग भी मजबूरी में गैरजिम्मेदार हो जाते हैं। हिमाचल में प्रतिदिन 370 मीट्रिक टन सूखा कचरा पैदा होता है, जिसके लगातार बढ़ते जाने की संभावना है।

शहरों में कम से कम कचरा एकत्र करने की व्यवस्थाएं तो हैं, आगे उसका निष्पादन कैसे हो,



यही समस्या आंशिक रूप से है। गांव की तो हालत और भी बुरी है। वहां तो कचरा एकत्रित करने की बुनियादी व्यवस्थाएं ही नहीं हैं। प्लास्टिक तो सब जगह पहुंच गया है। गांव में पहले तो केवल जैविक कचरा ही होता था, जिसका खाद बना लो या जला कर भी उतनी हानिकारक गैस नहीं निकलती थीं। अब गांववासी उसी पुरानी सोच के साथ चल कर कचरे की समस्या से पार नहीं पा सकते। अतः गांव में पंचायतों के माध्यम से कचरा प्रबंधन की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। पालमपुर की आईमा पंचायत की बहुप्रचारित कचरा प्रबंधन व्यवस्था भी अब बंद पड़ गई है। उसका अध्ययन करके

व्यवस्था बनानी पड़ेगी। मोटे तौर पर हर घर से महोने में एक बार कम से कम कचरा एकत्रित करने की व्यवस्था की जा सकती है, जिसके लिए पंचायत उपयुक्त राशि निर्धारित कर सकती है जो हर परिवार महोने के अंत में स्वयं कचरा इकठ्ठा करने वाले कार्यकर्ता को दे सकता है। पंचायतों में अधिकांश जगह कचरा एकत्रित करने के लिए स्टोर बना दिए गए हैं। अब उनके प्रयोग करने की ओर ध्यान देना होगा। गांव में जैविक कचरा उठाने की जरूरत नहीं है। उसका खाद बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। प्लास्टिक में भी मोटा प्लास्टिक कबाड़ी को बेचा जा सकता है। ठंडे की बोटलें भी बिक जाती हैं। उनके लिए केवल सख्ती

से जागरूक करने की जरूरत है। अगली चुनौती एकत्रित किए गए कचरे के निष्पादन की है। इसके लिए तो सरकार को दीर्घकालीन योजना बना कर काम करना चाहिए और उसके क्रियान्वयन के लिए हर स्तर पर पर्याप्त आर्थिक व्यवस्था करनी होगी। तकनीकी व्यवस्था अगली चुनौती है। नई-नई खोजें हो रही हैं। उनका उपयोग किया जाना चाहिए। एकमुखी समाधान से काम नहीं चलेगा। स्थानीय स्थितियों के अनुसार विविध प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करना पड़ेगा।

इसके लिए प्लास्टिक बनाने और प्लास्टिक में पैक सामान बेचने वाली कंपनियों को भी जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। कम से कम उन्हें

प्लास्टिक निष्पादन के लिए नई-नई तकनीकों की खोज और नवाचार के लिए फंड खड़ा करने के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। 'प्रदूषण फैलाने वाला ही भरपाई करे', यह तो न्यायालय द्वारा स्थापित सिद्धांत है। किंतु लागू तो नहीं हो रहा है। इसके लागू होने से सरकार पर अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा। किंतु इन दीर्घकालीन उपायों को लागू करते हुए तात्कालिक उपायों की ओर भी ध्यान देना जरूरी है, वरना पर्वतीय राज्यों की हालत खराब होने वाली है। यहां की हवा, पानी, और पर्यटकों को आकर्षित करने वाली सब प्राकृतिक देवें जल्द ही कचरे की भेंट चढ़ने वाली हैं।

होडा एमेज के टॉप वेरिएंट को है घर लाना, दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट के बाद कितनी जाएगी ईएमआई

परिवहन विशेष न्यूज

जापानी वाहन निर्माता Honda की ओर से कॉम्पैक्ट सेडान कार के तौर पर Honda Amaze को ऑफर किया जाता है। अगर आप भी इस कार के टॉप वेरिएंट को खरीदकर घर लाने का मन बना रहे हैं। तो दो लाख रुपये की Down Payment करने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देकर इस गाड़ी को घर लाया जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। जापान की वाहन निर्माता Honda की ओर से भारतीय बाजार में कॉम्पैक्ट सेडान कार के तौर पर Honda Amaze की बिक्री की जाती है। कंपनी की ओर से इसके टॉप वेरिएंट के तौर पर ZX को ऑफर किया जाता है। अगर इस वेरिएंट को खरीदने का मन बना रहे हैं तो दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट देने के बाद हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Honda Amaze ZX Price
होडा की ओर से अमेज के टॉप वेरिएंट के तौर पर ZX को ऑफर किया जाता है। कंपनी इस गाड़ी के ZX वेरिएंट को 9.99 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध करवा रही है। अगर इसे दिल्ली में खरीदा जाता है तो 9.99 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत के साथ ही इस पर रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस भी देना होगा। इस गाड़ी को खरीदने के लिए करीब 76 हजार रुपये का रजिस्ट्रेशन टैक्स, करीब 38 हजार रुपये इंश्योरेंस के देने होंगे। इनके अलावा फास्टिंग और अन्य चार्ज के



तौर पर 58.10 रुपये भी देने होंगे। जिसके बाद गाड़ी की दिल्ली में ऑन रोड कीमत 11.19 लाख रुपये हो जाती है।

दो लाख रुपये Down Payment के बाद कितनी EMI

अगर आप Honda Amaze के ZX वेरिएंट को आप खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में दो लाख रुपये की डाउन पेमेंट करने के बाद आपको करीब 9.19 लाख रुपये की राशि को बैंक से फाइनेंस करवाना

होगा। बैंक की ओर से अगर आपको नौ फीसदी ब्याज के साथ सात साल के लिए 9.19 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने सिर्फ 14797 रुपये की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

कितनी महंगी पड़ेगी Car

अगर आप नौ फीसदी की ब्याज दर के साथ सात साल के लिए 9.19 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 14797 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Honda Amaze के ZX वेरिएंट के

लिए करीब 3.23 लाख रुपये बतौर ब्याज देंगे। जिसके बाद आपको कार की कुल कीमत एक्स शोरूम, ऑन रोड और ब्याज मिलाकर करीब 14.42 लाख रुपये हो जाएगी।

किनसे होता है मुकाबला

Honda की ओर से Amaze को कॉम्पैक्ट सेडान कार सेगमेंट में लाया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Hyundai Aura, Maruti Dzire, Tata Tigor जैसी कारों के साथ होता है।

कैमरे ने काट तो नहीं दिया आपकी गाड़ी का चालान, ऑनलाइन ऐसे करें पता

आपकी गाड़ी पर नजर रखने के लिए ई-चालान सिस्टम की मदद यातायात पुलिस ले रही है। सड़कों पर लगे यह हाई-टेक कैमरे खुद-ब-खुद आपकी गाड़ी का चालान काट देते हैं। इनके जरिए चालान कटने पर वाहन मालिक को पता नहीं चलता है। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको e-Challan को ऑनलाइन चेक करने का तरीका बता रहे हैं।

नई दिल्ली। सरकार ने ट्रैफिक नियमों की अनदेखी को लेकर कड़ा कदम उठाया है। हाल ही में सरकार ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने और सजा में बदलाव किया है। इस बार सरकार ने ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने को 10 गुना बढ़ा दिया है। वहीं, ट्रैफिक चालान को आसान बनाने के लिए चौक-चौराहों पर कैमरे भी लगाए गए हैं, जो आपकी छोटी सी गलती पर भी चालान काट देते हैं। ई-चालान (e-Challan) सिस्टम से लोगों को यातायात नियमों का पालन करवाया जा रहा है। जिसे ध्यान में रखते हुए हम यहां पर आपको बता रहे हैं कि अगर आपकी गाड़ी का कैमरे से चालान काटता है, तो आप उसे ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं।

क्या है Traffic-e-Challan ?

यह एक इलेक्ट्रॉनिक चालान सिस्टम है, जिसके मदद से ट्रैफिक पुलिस अब अपने जरिए की गई कार्रवाई का डिजिटल रूप में रिकॉर्ड करती है। यह सिस्टम कैमरों के जरिए ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर स्वचालित रूप से चालान काटने का काम करती है। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर कोई वाहन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है, तो यह कैमरे उसकी पहचान करके चालान तैयार कर देते हैं और इसके बारे में वाहन मालिक को एक मैसेज के

जरिए बता भी देते हैं कि आपका ट्रैफिक चालान काटा गया है।

Traffic E-Challan ऑनलाइन चेक करने का तरीका

अगर आपको लगता है कि आपके वाहन का किसी कैमरे के जरिए ट्रैफिक चालान काटा जाता है, तो आप आसानी से अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर पर चेक कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप ऑनलाइन तरीके से ट्रैफिक चालान को चेक करने की प्रक्रिया के बारे में-

आधिकारिक ट्रैफिक वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले आपको अपने शहर या राज्य की ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

e-Challan सेक्शन पर क्लिक करें: वेबसाइट पर जाने के बाद आपको e-Challan या e-Traffic Violation सेक्शन पर क्लिक करना होगा।

वाहन विवरण दर्ज करें: इसके बाद आपको अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर (Vehicle Registration Number) को वहां पर दर्ज करना होगा।

CAPTCHA सही तरीके से भरें: इसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहे CAPTCHA को सही तरीके से भरना होगा और Submit पर क्लिक करना होगा।

चालान विवरण देखें: अगर आपके वाहन पर कोई चालान काटा गया है, तो वह आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। इसमें चालान की पूरी जानकारी, जैसे उल्लंघन की तारीख, चालान की राशि और उल्लंघन का विवरण सभी चीजें दिखाई देंगी।

भुगतान करें: अगर आप चालान का भुगतान करना चाहते हैं, तो यहीं पर आपको Pay Now का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक करके भुगतान कर सकते हैं।

होडा शाइन 100 वर्सेज हीरो स्प्लेंडर प्लस: इंजन, फीचर्स और परफॉर्मेंस में कौन बेस्ट

परिवहन विशेष न्यूज

भारतीय बाजार में कम्प्यूटर बाइक सेगमेंट में Honda Shine 100 और Hero Splendor Plus ऑफर की जाती है। यह दोनों ही बाइक इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकती हैं। वहीं यह दोनों ही एक-दूसरे को कड़ी टक्कर भी देती है। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको इन दोनों मोटरसाइकिल की तुलना करते हुए बता रहे हैं कि कौन बेहतर है।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में कम्प्यूटर बाइक सेगमेंट लोगों के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर है। इस सेगमेंट तकरीबन सभी दोपहिया बनाने वाली कंपनियां अपने मॉडल को पेश करती हैं। इस सेगमेंट में दो ऐसे नाम हैं, जो लोगों की चुनौतियां पर हमेशा रहते हैं, वे हैं, Honda Shine 100 और Hero Splendor Plus। हाल ही में होडा ने अपनी नई 2025 Shine 100 को लॉन्च किया है, जो कंपनी की सबसे सस्ती मोटरसाइकिल है। वहीं, हीरो की Splendor Plus इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक है। हम यहां पर आपको इन दोनों मोटरसाइकिल (Honda Shine 100 Vs Hero Splendor Plus) की तुलना करते हुए बता रहे हैं कि इंजन, फीचर्स और परफॉर्मेंस के मामले



मैं कौन बेहतर है।	Hero Splendor Plus	Honda Shine 100
1. इंजन और प्रदर्शन स्पेसिफिकेशन	98.98cc	97.20 cc
Honda Shine 100	98.98cc	97.20 cc
Hero Splendor Plus	98.98cc	97.20 cc
इंजन	7500 rpm पर 7.38 PS	8000 rpm पर 8.02 PS
टॉर्क	5000 rpm पर 8.05 Nm	6000 rpm पर 8.06 Nm
गियरबॉक्स	4-स्पीड	4-स्पीड
Honda Shine 100 में	98.98cc का तो Hero	

Splendor Plus में 97.2 cc का इंजन दिया गया है। Shine 100 में थोड़ी थोड़ा बड़ा इंजन मिलता है, लेकिन Splendor Plus से थोड़ा कम पावर जनरेट करता है। वहीं, Shine 100 का अधिकतम टॉर्क 5000 rpm पर जनरेट होता है, जो Splendor Plus से 1000rpm से पहले ही हो जाता है। इसकी वजह से शुरूआत में Shine 100 थोड़ी तेज जरूर हो सकती है, लेकिन बाद में Splendor Plus से पीछे हो सकती है।

2. सस्पेंशन और ब्रेकिंग स्पेसिफिकेशन
फ्रेम डायमंड टाइप ट्यूबलर डबल क्रैडल फ्रंट सस्पेंशन

टेलेस्कोपिक टेलस्कोपिक रियर सस्पेंशन प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी के साथ ट्विन रियर शॉक फ्रंट ब्रेक Drum 130 mm Drum 130 mm रियर ब्रेक Drum 110mm Drum 130 mm फ्रंट टायर 2.75-17 80/100-18 रियर टायर 3.00-17 80/100-18 दोनों ही बाइक में समान सस्पेंशन सेटअप दिया जाता है, जो रोजाना के कामकाज के लिए पर्याप्त है।

सालों से चला रहे हैं कार, नहीं जानते सही से बैठने का तरीका, परेशानी के साथ होते हैं ये नुकसान



कार चलाते हुए बैठने का ये है सही तरीका

परिवहन विशेष न्यूज

अब सर लोग कार तो चलाते हैं लेकिन इस दौरान पीठ में काफी दर्द महसूस होता है। अगर आपके साथ भी कार चलाते हुए ऐसी समस्या होती है तो इस बात की पूरी संभावना है कि ड्राइविंग के दौरान आपके बैठने का तरीका सही नहीं हो। कार चलाते हुए किस तरह से बैठना आपके और आपकी सेहत के लिए बेहतर हो सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। कार चलाना तो हर किसी को थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आ जाता है। लेकिन कार चलाते हुए सही तरह से बैठने की जानकारी काफी कम लोगों को होती है। सही तरह से बैठकर कार न चलाने के कारण लंबे समय में कई तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं, जिनके कारण कार चलाना काफी मुश्किल हो जाता है। कार चलाते हुए किस तरह से बैठना (Car Driving Tips) चाहिए। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

ज यादा पीछे न झुकाएं सीट

कार चलाते हुए आपको लंबे समय तक सीट पर ही बैठना होता है। इसलिए सीट को पीछे की ओर ज्यादा झुकाना नहीं चाहिए। जानकारों के मुताबिक अगर आप कार चलाते हुए सीट को 100 से 110 डिग्री के आस-पास तक रिक्लाइंड (Seatback reclined at 100-110°) करते हैं तो इससे आपको आराम तो मिलता ही है साथ ही पीठ में समस्या नहीं होती।

स्टेयरिंग व्हील से बनाएं दूरी

कुछ लोग कार चलाते हुए स्टेयरिंग के काफी पास रहते हुए कार को चलाते हैं। ऐसा करना न सिर्फ हादसे के समय आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है बल्कि इससे आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचता है। जानकारों के मुताबिक अगर कार चलाते हुए स्टेयरिंग से 10 इंच के आस-पास की दूरी (At least 10 inches from the steering wheel for safety) रखी जाए तो इससे कार चलाने में आसानी तो होती ही है साथ ही सुरक्षा भी मिलती है।

लोअर बैक का रखें ध्यान

कार चलाते हुए कई लोग अपनी लोअर बैक का ध्यान नहीं रखते हैं। इससे उस एरिया में दर्द होने लगता है और लगातार कार चलाने में समस्या होती है। इसके लिए जब भी सीट पर बैठें तो अपने लोअर बैक को अच्छी तरह से सीट के पास रखें। इस तरह आपको ज्यादा बेहतर लॉन्ग स्पॉर्ट (Lower back fully supported with lumbar support) मिलेगा और कार में ज्यादा समय तक बैठने में आसानी होगी।

पैडल दबाने का सही तरीका जानें

अगर आप अपनी सीट के साथ ही ऊपर बताई बातों का पालन करते हैं तो पैडल दबाने का सही तरीका खुद ही आ जाएगा। कार चलाते हुए पैडल दबाते समय घुटनों का 120 डिग्री के आस-पास होना जरूरी (Knees bent at 120° when pressing pedals) होता है। ऐसा होता है तो न सिर्फ आप अच्छी तरह से पैडल दबा सकते हैं, बल्कि आपको इसके लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती।

कितनी दमदार होगी फॉक्सवेगन टाइगुन R-Line, लॉन्च से पहले सामने आ गई इंजन से फीचर्स तक की जानकारी

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। जर्मनी की वाहन निर्माता Volkswagen की ओर से भारतीय बाजार में जल्द ही नई एसयूवी के तौर पर Volkswagen Tiguan R-Line को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च से पहले एसयूवी के इंजन, पावर, फीचर्स और डिजाइन की जानकारी सामने आ गई है। इसमें कितनी दमदार इंजन मिलेगा, किस तरह के फीचर्स और डिजाइन को दिया जाएगा। कब तक इसे लॉन्च किया जाएगा। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

जल्द लॉन्च होगी नई एसयूवी फॉक्सवेगन की ओर से भारत में
जल्द ही नई एसयूवी को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। एसयूवी के लॉन्च से पहले एसयूवी के कुछ फीचर्स और इंजन की जानकारी सामने आ गई है।

कितना दमदार होगा इंजन
कंपनी की ओर से एसयूवी के लॉन्च से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर इंजन से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक इस एसयूवी में दो लीटर की क्षमता के

टीएसआई पेट्रोल इंजन को दिया जाएगा। जिससे इसे 204 पीएस की पावर और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा।

कैसे होंगे फीचर्स

वेबसाइट पर इंजन की जानकारी के साथ ही कुछ फोटो को भी सार्वजनिक किया गया है। जिसके मुताबिक एसयूवी में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाएगा। इसमें फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, एलईडी हेडलाइट्स, कनेक्टिड टेल लाइट्स, फ्रंट में कनेक्टिड एलईडी डीआरएल, फ्रंट में आर बैजिंग, बड़ी फ्रंट ग्रिल, साइड प्रोफाइल में आर बैजिंग, रूफ रेल और शार्क फिन एंटीना को दिया जाएगा। इंटीरियर में भी ग्रे के साथ ब्लैक-ब्लू थीम को रखा जाएगा। इसके अलावा इसमें बड़ा इन्फोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, ऑटो एसी, एपल कार प्ले, एंड्राइड ऑटो, ड्राइविंग के लिए मोड्स, पार्क असिस्ट, क्रूज कंट्रोल, ADAS, ड्राइविंग के लिए सामान्य और स्पोर्ट्स मोड, एबीएस, ईबीडी, छह एयरबैग जैसे कई फीचर्स

को दिया जाएगा।

प्री-बुकिंग हुई शुरू

Volkswagen Tiguan R-Line के लिए कंपनी की ओर से प्री-बुकिंग को शुरू कर दिया गया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन डीलरशिप के जरिए इस एसयूवी को प्री-बुक करवाया जा सकता है। एसयूवी को कुल छह रंगों के विकल्प में ऑफर किया जाएगा, जिसमें Persimmon Red Metallic, Nightshade Blue Metallic, Grenadilla Black Metallic, Oryx White Mother of Pearl Effect, Cypressino Green Metallic और Oyster silver Metallic जैसे रंग शामिल होंगे।

कब होगी लॉन्च

कंपनी की ओर से 14 अप्रैल 2025 को औपचारिक तौर पर नई एसयूवी को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया जाएगा। बाजार में इसका मुकाबला Toyota Fortuner Legender, MG Gloster, BMW X1 और जल्द लॉन्च होने वाली नई Skoda Kodiaq जैसी एसयूवी से होगा।



'जब तक पुराने नियम समझते हैं, तब तक...!', व्यापारियों के लिए क्यों झंझट बना जीएसटी?

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली: 30 जून-01 जुलाई, 2017 की मध्य रात्रि को संसद की संयुक्त बैठक में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में देश में कर ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव का घंटा बजाया तो यह माना गया कि अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था से जुड़े हजारों टैक्स अधिकारियों की नींद टूट जाएगी।

साथ ही जीएसटी प्रणाली लागू होने से कारोबारियों को लालफीताशाही के दौर से मुक्ति और एक सुगम तथा किफायती व्यवस्था मिल जाएगी और उन पर टैक्स संबंधी बोझ कम होगा। मगर जीएसटी प्रणाली लागू होने के करीब आठ साल होने के बावजूद व्यापारी-कारोबारी जीएसटी नियम में हर महीने हो रहे बदलाव से लेकर विभागीय कर्मचारियों के बर्ताव से परेशान और क्षुब्ध दिखाई दे रहे हैं।

नियमों में लगातार होने वाले बदलाव और एक ही प्रकार के उत्पादों पर अलग-अलग जीएसटी की दरें होने से कारोबारियों से जीएसटी रिटर्न भरने में गलती हो जाती है और फिर उन्हें नोटिस से लेकर अन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। जीएसटी के कई जटिल प्रविधानों को समझने के लिए कारोबारी विशेषज्ञों का सहारा लेने को बाध्य हो रहे हैं जिसकी एवज में उन्हें मोटी फीस चुकानी पड़

रही है।

क्या है कारोबारियों की शिकायत?
कारोबार-व्यापार से जुड़े लोगों के अनुसार इसे छोटे कारोबारियों की लागत बढ़ रही है। कारोबारियों की शिकायत है कि वे पूरे माह जीएसटी रिटर्न भरने में लगे रहते हैं अन्यथा लाखों की देनदारी का नोटिस आ जाता है।
कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अध्यक्ष बी.सी. भरतिया कहते हैं, "महीने के 10 तारीख को पहला रिटर्न भरो, 12-13 तारीख तक उस रिटर्न का विभाग से जवाब आता है, फिर उसे वेरिफाई करो और फिर 20 तारीख को फाइनल रिटर्न भरो। एक-एक बिक्री और एक-एक खरीद को रजिस्टर करना होता है। आपदा या विशेष परिस्थिति में अगर 20 तारीख तक जीएसटीआर दाखिल नहीं किया गया तो सिस्टम अपने आप जुर्माना लगा देता है। फिर उसे वापस लेने के लिए चक्कर लगाओ।"

भरतिया कहते हैं,

जब जीएसटी प्रणाली लागू हुई थी तो उन्हें यह बताया गया था कि पूरे देश के व्यापारी सिर्फ अपनी-अपनी बिक्री की जानकारी सरकार को देंगे। इससे सरकार के पास खरीदारी का पूरा ब्योरा अपने-आप आ जाएगा। कारोबारियों के मुताबिक साधारण पापकान की जीएसटी दरें और चाकलेटी क्रीम लगे पापकान की जीएसटी दरें अलग-अलग हैं। रोटी की दर अलग है तो



पराठे की अलग। अलग-अलग बन और बटन लेने पर जीएसटी दर कम है और दोनों को साथ मिलाने पर यह दर बढ़ जाती है। इस प्रकार की भ्रामक स्थिति में कारोबारी गलत रिटर्न भर देते हैं और फिर उन्हें देनदारी का नोटिस आ जाता है और विभागीय कर्मचारी कारोबारियों के पीछे पड़ जाते हैं।

कारोबारियों को आ रही इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने में समस्याएं

कारोबारियों के मुताबिक शुरू में जीएसटी का प्रारूप साधारण था, लेकिन टैक्स चोरी पकड़ने के नाम पर इनमें नए-नए प्रविधान जुड़ते चले गए। व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने में हो रही

दिकतों को लेकर है।

कोई कारोबारी किसी दूसरे कारोबारी से माल खरीदता है और दूसरा कारोबारी अगर समय पर जीएसटी रिटर्न नहीं भरता है तो पहले कारोबारी का इनपुट टैक्स रिटर्न फंस जाता है। अगर दूसरा कारोबारी फ्राड निकल जाता है तो भी पहले कारोबारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं

मिल पाता है।

कारोबारियों की शिकायत है जो कारोबारी फ्राड कर रहे हैं या जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी सरकार ने ही जीएसटी व्यवस्था में पंजीकृत किया है, फिर इसमें उनकी क्या गलती है कि उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट रोक लिया जाता है।

'जब तक पुराने नियम समझते हैं, तब तक नए नियम आ जाते हैं'

दिल्ली सदर बाजार व्यापारी संघ के अध्यक्ष देवराज बवेजा कहते हैं, "पिछले आठ सालों में सैकड़ों नियम बदल चुके हैं और जब तक व्यापारी पुराने नियम को समझते हैं, नए नियम आ जाते हैं। एचएस कोड को भी समझना छोटे व्यापारियों के लिए परेशानी की बात है।"

असल में जिन वस्तुओं का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार होता है, उन सभी का हार्मोनाइज्ड सिस्टम या एचएस कोड तय किया जाता है और उन वस्तुओं की जीएसटी दरें भी एचएस कोड के हिसाब से तय होती हैं।

टैक्स एक्सपर्ट और चार्टर्ड एकाउंटेंट एम.के. गुप्ता कहते हैं कि पहले कारोबारियों के जीएसटी का ऑडिट अनिवार्य था। अब ऑडिट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। ऐसे में कारोबारी गलती कर बैठते हैं और दो-तीन साल पुरानी गलती से जुड़े उन्हें नोटिस आ रहे हैं तथा उनकी परेशानियां में इजाफा कर रहे हैं।

तूफानी मूड में शेयर बाजार, सेंसेक्स ने लगाई 730 अंक की छलांग; इस वजह से आई तेजी



सेंसेक्स और निफ्टी में आज फिर उछाल देखने को मिली है। निफ्टी 200 अंक चढ़ गया। बीते हफ्ते जबरदस्त बढ़त लेने के बाद आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला Sensex खुलने के साथ ही 400 अंक से ज्यादा उछला और बाद में 700 अंक पार कर गया। वहीं निफ्टी भी तेजी के साथ 23 850 के पार चला गया।

नई दिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में लगातार 7 वें दिन जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल देखने को मिली है। सेंसेक्स 78500 के करीब पहुंच गया है, अभी 730 अंक की उछाल के साथ बढ़ा है।

निफ्टी 250 अंक पहुंच गया। बीते हफ्ते जबरदस्त बढ़त लेने के बाद आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला Sensex खुलने के साथ ही 400 अंक से ज्यादा उछला।

निफ्टी इंडेक्स करीब 80 अंकों की तेजी के साथ 23800 के पास पहुंच गया है। एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई

हरे निशान में कारोबार कर रहा। वहीं, अमेरिकी वायदा बाजार सपाट ट्रेड कर रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, एनटीपीसी, SBI, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स 4.5 प्रतिशत तक पहुंच गए हैं।

क्या कहता है BSE का सेंसेक्स?

शेयर मार्केट (Stock Market) के ओपन होने के साथ ही बीएसई का सेंसेक्स अभी 78,669.43 के स्तर पर है। वहीं कल ये अपने पिछले बंद 76,905.51 की तुलना में जोरदार तेजी लेते हुए 77,456.27 के स्तर पर खुला और देखते ही देखते 77,498.29 तक पहुंच गया था। Sensex की ये रफ्तार कारोबार बढ़ने के साथ और बढ़ती गई। अभी तक 1000 अंक की उछाल के साथ 77,907.42 के स्तर पर कारोबार करता दिखा।

मार्केट में क्यों आ रहा उछाल?

आरबीआई के रेट कट की उम्मीद: अमेरिकी फेड की बैठक के बाद अब आरबीआई से भी रेट कट की चर्चा जोर पर है।

विदेशी और घरेलू निवेशक शेयर बाजार में जमकर पैसा लगा रहे हैं।

ग्लोबल कंपनी ने भारत की GDP और महंगाई को लेकर पॉजिटिव आउटलुक दिया है।

भारतीय स्टॉक मार्केट ने फिर दिखाई अपनी ताकत, दुनियाभर के बाजारों को पीछे छोड़ बना टॉप परफॉर्मर

दुनिया के दस सबसे बड़े इक्विटी बाजारों में भारत का शेयर बाजार मार्च में सबसे ज्यादा बढ़ा। डॉलर के संदर्भ में बात करें तो इसने 9.4 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की। शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार बॉंबे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध सभी कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण फरवरी के अंत में लगभग 4.39 ट्रिलियन डॉलर था जो अब बढ़कर लगभग 4.8 ट्रिलियन डॉलर हो गया।

मुंबई। दुनिया के दस सबसे बड़े इक्विटी बाजारों में भारत का शेयर बाजार मार्च में सबसे ज्यादा बढ़ा। डॉलर के संदर्भ में बात करें तो इसने 9.4 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की।

लगातार पांच महीनों की गिरावट के बाद यह चार सालों में सबसे मजबूत रैली है।

शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, बॉंबे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध सभी कंपनियों का कुल बाजार पूंजीकरण फरवरी के अंत में लगभग 4.39 ट्रिलियन डॉलर था, जो अब बढ़कर लगभग 4.8 ट्रिलियन डॉलर हो गया।

मई 2021 के बाद यह सबसे बड़ी मासिक उछाल है। सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में जहां भारत ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं जर्मनी 5.64 प्रतिशत की वृद्धि और 2.81 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के बाजार पूंजीकरण के साथ दूसरे स्थान पर रहा। जापान और हांगकांग के शेयर बाजारों



में क्रमशः 4.9 प्रतिशत और चार प्रतिशत की वृद्धि हुई।

इन देशों के शेयर बाजारों में भी आई तेजी

फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के शेयर बाजारों में भी मामूली वृद्धि दर्ज की गई। इसके विपरीत, दुनिया के सबसे बड़े इक्विटी बाजार अमेरिका में 3.7 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, जबकि सऊदी अरब के बाजार में 4.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। मार्च में भारतीय इक्विटी बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी में 5-5 प्रतिशत की तेजी आई, जबकि व्यापक बीएसई मिडकैप और स्मालकैप सूचकांकों में क्रमशः 8.4 प्रतिशत और 9.8 प्रतिशत की तेज बढ़त दर्ज की गई।

आरबीआई द्वारा जल्द ही ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद के साथ अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा 2025 में दो बार ब्याज दरों में कटौती के संकेत ने भी निवेशकों को धारणा में सुधार किया है।

रेपो रेट में एक और कटौती कर सकता है आरबीआई

भारत की खुदरा मुद्रास्फीति आरबीआई के मध्यम अवधि के लक्ष्य चार प्रतिशत से नीचे रही है। इससे इन उम्मीदों को बल मिला है कि केंद्रीय बैंक अप्रैल में होने वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में रेपो रेट में एक और कटौती का एलान कर सकता है। विश्लेषकों को आरबीआई से सिस्टम में नकदी बढ़ाने के उपायों के एलान की भी उम्मीद है।

केंद्रीय बैंक ने पहले ही रेपो नीलामी और खुले बाजार परिचालन जैसे विभिन्न कदमों के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में लगभग तीन लाख करोड़ रुपये डाले हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार में तेजी के बाद थोड़े समय के लिए निवेश करने वाले निवेशक मुनाफावसूली कर सकते हैं, जबकि दीर्घकालिक निवेशकों को बाजार में बने रहना चाहिए। इसके पीछे उनका तर्क है कि

अगर कारपोरेट आय मजबूत बनी रहती है तो आगे और तेजी की संभावना है।

स्टॉक मार्केट के लिए सबसे बुरा दौर बीत चुका है: रामदेव अग्रवाल

सोमवार को भारतीय शेयर बाजारों के दो महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के चेयरमैन और सह-संस्थापक रामदेव अग्रवाल ने कहा कि अब स्टॉक मार्केट के लिए सबसे बुरा दौर बीत चुका है और अच्छे दिन वापस आ गए हैं। अग्रवाल ने कहा कि निवेशकों को आरबीआई के ब्याज दरों में तेजी के बाद बाजार में तेज उछाल देखा गया। पिछले एक सप्ताह में निफ्टी और सेंसेक्स में पांच प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई है। हालिया तेजी में मिडकैप और स्मालकैप शेयरों का सबसे ज्यादा योगदान रहा।

ब्रोकरेज फर्म ने सुझाव दिया कि निवेशकों को अगले छह महीनों में शेयरबढ़ तरीके से मिड और स्मालकैप शेयरों में निवेश करते हुए एक-मुश्त निवेश के माध्यम से लार्ज-कैप और हाइब्रिड फंड में निवेश करना जारी रखना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि खपत को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से आर्थिक विकास को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

क्या मैच्योरिटी से पहले निकाले जा सकते हैं पैसे? जानिए नियम

महिला सम्मान सेविंग स्कीम खास तौर पर महिलाओं के लिए डिजाइन की गई है। इसके जरिए महिला निवेशक अच्छा खासा फंड तैयार कर सकती है। इस स्कीम की अवधि 2 साल की है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि निवेश किया गया अमाउंट हमें इमरजेंसी के लिए चाहिए हो तो क्या अवधि पूरी होने से पहले पैसे निकाले जा सकते हैं?

नई दिल्ली। पोस्ट ऑफिस एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म माना जाता है। इसमें पैसा डूबने का खतरा नहीं रहता। पोस्ट ऑफिस के तहत कई तरह की स्कीम्स ऑफर की जाती हैं। इनमें से ही एक है, पोस्ट ऑफिस महिला सम्मान बचत योजना (Mahila Samman Saving Certificate)। इस स्कीम की अवधि आमतौर पर 2 साल की होती है। लेकिन हो सकता है, इमरजेंसी पड़ने पर हमें अवधि पूरी होने से पहले पैसे निकाले जा सकें।



उठता है कि क्या एमएसएससी के तहत अवधि पूरी होने से पहले पैसे निकाले जा सकते हैं?

क्या मैच्योरिटी से पहले पैसे निकाल सकते हैं?

पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार अगर महिला निवेशक चाहे तो योजना की अवधि पूरी होने से पहले पैसे निकाल सकती है। हालांकि इसे लेकर भी कुछ नियम हैं। कोई भी निवेशक महिला सम्मान बचत योजना के तहत 1 साल बाद निवेश करने के बाद बीच में ही पैसे निकाल सकते हैं।

लेकिन आप सिर्फ 40 फीसदी

तक ही राशि निकाल सकते हैं। ये 40 फीसदी पैसे कुल अमाउंट पर कैलकुलेट होता है। जिनमें एक साल एक अंतराल में मिलने वाला ब्याज भी शामिल होता है।

उदाहरण के लिए- मान लीजिए कोई निवेशक महिला सम्मान बचत योजना के तहत 2 लाख रुपये निवेश करता है, तो एक साल के भीतर उसके खाते में 2,15,427 रुपये बन जाएंगे। इन्हें 2,15,427 पर 40 फीसदी के हिसाब से निकासी रकम कैलकुलेट की जाती है। जिसका मतलब हुआ कि खाते में 2,15,427 होने पर निवेशक लगभग 86 हजार

रुपये ही निकाल पाएंगे। वहीं अगर निवेशक को कोई गंभीर बीमारी हो, तो ऐसे में पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर आपको प्रीसिपल अमाउंट पर ही रिटर्न मिलता है। इसके साथ ही निवेशक 6 महीने बाद भी पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे में 2 फीसदी कम रिटर्न मिलता है।

कैसे निकालें पैसे?

अगर आप स्कीम की अवधि पूरी होने से पहले पैसे निकालना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने पास स्थित पोस्ट ऑफिस में जाकर एक

निकासी अनुरोध फॉर्म भरना होगा। इसके साथ ही एक पहचान पत्र जमा करना होगा।

कितना मिलता है रिटर्न?
महिला सम्मान सेविंग स्कीम में आपको 7.5 फीसदी तक रिटर्न मिल जाता है। ये ब्याज तिमाही के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। स्कीम के तहत मिलने वाला रिटर्न और प्रीसिपल अमाउंट आपको अवधि पूरी होने के बाद ही मिलता है।

वहीं इस स्कीम को 1000 रुपये के साथ शुरू किया जा सकता है। वहीं अधिकतम आप इसमें 2 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं।

नई दिल्ली। Samsung Galaxy S25 Ultra स्मार्टफोन भारत में साल की शुरुआत में लॉन्च हुआ था। सैमसंग का यह स्मार्टफोन पिछले साल के Galaxy S24 Ultra का सक्सेसर है। सैमसंग का लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन क्वालकॉम के Snapdragon 8 Elite चिपसेट के साथ पेश किया गया है, जो One UI 7 कस्टम स्किन पर रन करता है। फिलहाल Samsung Galaxy S25 Ultra स्मार्टफोन पर 11 हजार रुपये का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। यहां हम आपको सैमसंग के इस स्मार्टफोन पर मिल रही डील के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

Samsung Galaxy S25 Ultra बैंक ऑफर्स
Samsung Galaxy S25 Ultra स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसे 1,29,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया है। इस फोन का दूसरा वेरिएंट 512 जीबी स्टोरेज के साथ 1,41,999 रुपये और टॉप वेरिएंट 1TB स्टोरेज के साथ 1,65,999 रुपये की कीमत में आता है। सैमसंग के इस फोन पर एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से फुल पेमेंट करने पर 11 हजार रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं, ईएमआई पेमेंट पर 9000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस बैंक डिस्काउंट के साथ सैमसंग के इस फोन की कीमत में खरीदा जा सकता है। इस ऑफर का बोनफिट सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट, अमेज़न, रिलायंस डिजिटल और फ्लिपकार्ड से उठाया जा सकता है। Samsung Galaxy S25 Ultra स्मार्टफोन Titanium Silverblue, Titanium Gray/Titanium Black, और Titanium Whitesilver कलर ऑप्शन में बिक्री के लिए अपलब्ध है। इसके साथ ही सैमसंग की वेबसाइट पर तीन

सैमसंग दे रहा 11,000 रुपये का डिस्काउंट, 200MP कैमरा वाले स्मार्टफोन को सस्ते में खरीदने का मौका

सैमसंग गलैक्सी एस 25 अल्ट्रा स्मार्टफोन पर तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। सैमसंग का यह फोन इस साल की शुरुआत में ही लॉन्च किया गया था। एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से फुल पेमेंट करने पर 11 हजार रुपये और ईएमआई पेमेंट पर 9000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। यहां हम सैमसंग के इस फोन मिलने वाले ऑफर के बारे में डिटेल जानकारी दे रहे हैं।

नई दिल्ली। Samsung Galaxy S25 Ultra स्मार्टफोन भारत में साल की शुरुआत में लॉन्च हुआ था। सैमसंग का यह स्मार्टफोन पिछले साल के Galaxy S24 Ultra का सक्सेसर है। सैमसंग का लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन क्वालकॉम के Snapdragon 8 Elite चिपसेट के साथ पेश किया गया है, जो One UI 7 कस्टम स्किन पर रन करता है। फिलहाल Samsung Galaxy S25 Ultra स्मार्टफोन पर 11 हजार रुपये का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है। यहां हम आपको सैमसंग के इस स्मार्टफोन पर मिल रही डील के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

S25 Ultra बैंक ऑफर्स
Samsung Galaxy S25 Ultra स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसे 1,29,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया है। इस फोन का दूसरा वेरिएंट 512 जीबी स्टोरेज के साथ 1,41,999 रुपये और टॉप वेरिएंट 1TB स्टोरेज के साथ 1,65,999 रुपये की कीमत में आता है। सैमसंग के इस फोन पर एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड से फुल पेमेंट करने पर 11 हजार रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं, ईएमआई पेमेंट पर 9000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस बैंक डिस्काउंट के साथ सैमसंग के इस फोन की कीमत में खरीदा जा सकता है। इस ऑफर का बोनफिट सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट, अमेज़न, रिलायंस डिजिटल और फ्लिपकार्ड से उठाया जा सकता है। Samsung Galaxy S25 Ultra स्मार्टफोन Titanium Silverblue, Titanium Gray/Titanium Black, और Titanium Whitesilver कलर ऑप्शन में बिक्री के लिए अपलब्ध है। इसके साथ ही सैमसंग की वेबसाइट पर तीन

स्पेशल कलर - Titanium Jetblack, Titanium Jadegreen, और Titanium Pinkgold भी उपलब्ध है। **Samsung Galaxy S25 Ultra के स्पेसिफिकेशन**
सैमसंग के इस फोन में 6.9-इंच का Dynamic LTPO AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz और पीक ब्राइटनेस 2600 निट्स है। इस डिस्प्ले में Corning Gorilla Armor 2 का प्रोटेक्शन मिलता है। सैमसंग का यह फोन क्वालकॉम के फ्लैगशिप Snapdragon 8 Elite चिपसेट के साथ बाजार में उतारा गया है। सैमसंग के Galaxy S25 Ultra स्मार्टफोन में कई एआई फीचर्स मिलते हैं। इस फोन में क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसका प्राइमरी कैमरा 200MP का है, जिसके साथ 50MP का अल्ट्रावाइड कैमरा, 50MP टेलीफोटो कैमरा और 10MP सेकेंडरी टेलीफोटो कैमरा सेसर दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में 12MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसके साथ ही फोन में 5000mAh की बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है।

